आकाशवाणी केन्द्र शिमला

17.07.2025 / प्रादेशिक समाचार / 11:00बजे

राष्ट्रपति–स्वच्छ सर्वेक्षण

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस कार्यक्रम में शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया जायेगा और स्वच्छ भारत मिशन–शहरी को आगे बढ़ाने के प्रयासों को मान्यता दी जायेगी। इस वर्ष ये पुरस्कार चार श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे, जिनमें सुपर स्वच्छ लीग शहर और अधिक जनसंख्या वाले पांच शहरों में से शीर्ष तीन स्वच्छ शहर शामिल हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएँगे। मंत्रालय ने कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 में शहरी स्वच्छता और सेवा वितरण का आकलन करने के लिए एक स्मार्ट और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो शहरों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन का संपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करता है।

प्रधानमंत्री

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और ये योजना इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न केवल पिछड़े जिलों में फसल–उत्पादन में वृद्धि होगी हालाकि खाद्य उपलब्ध कराने वालों की आय में भी बढोत्तंरी होगी। वर्ष 2025–26 के बजट प्रस्तावों में प्रधानमंत्री धन–धान्य कृषि योजना के अंतर्गत एक सौ जिलों के विकास के लिए इस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इस योजना को 11 विभागों में 36 वर्तमान योजनाओं के माध्यम से अन्य राज्यों, योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय सहभागिता के साथ लागू किया जाएगा।

अश्विनी– सीएससी दिवस

इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश के दस लाख नागरिकों को निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें ग्राम स्तर के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित जन सेवा केन्द्र दिवस कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सी एस सी देश के लगभग 90 प्रतिशत गाँवों तक पहुँच चुका है। वैष्णव ने सभी ग्रामीण उद्यमियों से नागरिकों को आई आर सी टी सी सेवाएँ प्रदान करने का आग्रह किया।

ए आई मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस ए आई मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है, करीब दस लाख लोगों को एआई स्किल्स में तैयार करेंगे। उसमें साढे पांच लाख नियरलीस अपने हैं आप सबको सबसे पहले उसमें प्रीफेंस दी जाएगी।

जगत सिंह नेगी

राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भूमिहीन हुए लोगों को रहने व खेती के लिए जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केंद्र से एफसीए एक्ट 1980 में संशोधन की मांग की है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर करेगी।

लोगों की हजारों बीघा जमीन बह गई। लोगों के पास अपने लिए कोई ऑप्शन नहीं बची। जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसमें हमें वन भूमि लोगों को चाहे उनकी बह गई जमीन के बदले देना पड़े या उनको आशियान बना कर देना पड़े तो ये अभी प्रस्ताव हमने विधानसभा से केंद्र को भेजा है और अभी हम सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर करने जा रहे हैं सरकार के पक्ष में। हिमाचल में जो है सारी जमीन वनभूमि मानी गई है उसमें एक तो वनभूमि की जो परिभाषा है उसको लेकर हम आगे जा रहे हैं और एफसीए जो है संशोधन को लेकर आगे जा रहे हैं।

पोर्टल

कृषि विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक मशीनरी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एग्री मशीनरी पोर्टल कल 18 जुलाई से सक्रिय किया जाएगा। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इसके माध्यम से प्रदेश के किसान विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों को नई, आधुनिक और उन्नत किस्म की कृषि मशीनरी व उपकरण उपलब्ध करवाना है। प्रवक्ता ने किसानों से इस पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।

मौसम

मानसून के सक्रिय रहने से राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज वर्षा का क्रम रूक–रूक कर जारी है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा कुल्लू व मंडी जिलों में 19 जुलाई तक बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले दिनों भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़ व बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में अवरूद्ध सड़क मागों को खोलने के अलावा बिजली व पेयजल योजनाओं को बहाल करने का कार्य भी जारी है।

विरोध प्रदर्शन

सीटू और किसान सभा के बैनर तले शिमला फोरलेन के प्रभावितों ने चक्कर स्थित एन.एच.ए. आई. के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा ने कहा कि

फोरलेन निर्माण कर रही कम्पनियों द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है जिससे कैथलीघाट से ढली तक 9 पंचायतों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैज्ञानिक कटिंग और अवैध डम्पिंग से लोगों के घर, खेत, रास्ते और पेयजल स्रोत प्रभावित हुए हैं।